(vii) Budgetary support has also been provided to the sick fertiliser undertakings in the central public sector to enable them to sustain their production.

A statement indicating projects currently under implementation is attached (See below) With the commissioning of these projects, the annual indigenous production capacity will get augmented by 41.63 Lakh Metric Tonnes in the case of urea and 1.84 Lakh Metric Tonnes in the case of Complex fertilisers.

Statement

Requirement of Nitrogen, Phosphate and Potash

Sl. No.	Name of the Company/ Cooperative	Location	Estimated Capital Cost (Rs. Crores)	Product	Incremental Production Envisaged (In Lakh MTPA)
1.	Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. (IFFCO)	Aonla (U.P.)	960.00	Urea	7.26
2.	IFFCO	Kalol (Gujarat)	119.00	Urea	1.50
3.	IFFCO	Phulpur (U.P.)	993.00	Urea	7.26
4.	National Fertilizers Ltd. (NFL)	Vijaipur (M.P.)	987.30	Urea	7.26
5.	Madras Fertilizers Ltd. (MFL)	Manali (Madras)	487.30	Urea NPK	0.76 1.84
6.	Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd.	Kakinada (A.P.)	969.98	Urea	4.95
7.	National Fertilizers Ltd. (NFL)	Nangal (Punjab)	50.00	Urea	2.14
8.	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (RCF)	Thall Phase-I Phase-II	49.00 93.00	Urea Urea	1.65 1.10
9.	Tata Chemicals Limited (TCL)	Babrala (U.P.)	1251.76	Urea	7.75

विशाखापटनम से नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना

3238. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें विशाखापटनम से मद्रास, विजयवाड़ा और भुवनेश्वर जैसे अन्य बहुत से स्थानों के लिए नई रेलगाड़ियां चलाये जाने के अनुरोध किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिये हैं;

(ग) क्या सरकार विद्यमान रेल गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने और उनमें अन्य सुविधाएं बढ़ाकर तत्काल राहत प्रदान कर रही है; और

(घ) क्या विशाखापटनम से चलायी जाने वाली कुछ रेलगाड़ियों में विशेष डिब्बे जोड़ कर आरक्षण कोटा में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इनकी जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों पर नई गाड़ियों, सवारी डिब्बों सहित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है, जो यातायात के औचित्य और परिचालनिक कठिनाई/संसाधनों की तंगी पर निर्भर करती है। अक्तूबर, 96 से 7003/7004 फलकनुमा एक्सप्रेस की बारबारता सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन किए जाने का प्रस्ताव है। बहरहाल, विशाखापत्तनम के रास्ते से चल रही गाड़ियों के सवारी डिब्बों में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

National Policy for Empowerment of Women

3239. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has expressed his keenness to formulate a national policy for the empowerment of women to direct strategies for elimination of discrimination against them;

(b) if so, the main points of the national policy; and

(c) by when the same is likely to be announced?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) to (c) The Government of India, Department of Women and Child Development has prepared a draft of the National Policy for the Empowerment of Women. A copy of the draft is annexed. *[See Appendix 178, annexure a 78]* The policy will be announced upon approval.

Act on Public Liability Insurance for Hazardous Chemicals

3240. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state the reasons for which the Act brought by the Minbistry in 1990—the Public Liability Insurance for Hazardous Chemicals — and passed by Parliament in 1990, ratified by the President of India in January 1991, has not been introduced into the Insurance Sector as yet?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPTAIN JAI NARAYAN PRASAD NISHAD): The Public Liability Insurance Act, 1991 has been gazetted with a view to ensure that owners handling notified hazardous chemicals takeout insurance policy to pay prescribed amount of relief in the event of death or injury to any person (other than a workman) or damage to any property resulting due to a chemical accident in the installation.

The Act is being administered by the General Insurance Corporation and its subsidiaries since 1991. As per information made available by them, till date 6837 policies have been issued and an amount of Rs. 22.44 crore has been collected as premium, The Same amount has also been collected as contribution to the Environment Relief Fund. Relief paid against claims so far in respect of six accidents amounts to Rs. 16,000.

इंटरसिटी एक्सप्रेस में खान-पान सुविधा

3241. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हजरत निजामुद्दीन और इंदौर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रियों को खानपान की किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, और

(ख) क्या इस रेलगाड़ी में रसोईयान सुविधा उपलब्ध है, और यदि नहीं, तो इस सुविधा के कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) इस गाड़ी के यात्रियों का चाय, नाश्ता, रात का भोजन पानी आदि जैसी खानपान सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

(ख) जी हां?